

&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

- लोकसभा ने कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक, 2025 को धनिमत से पारित कर दिया।
- सरकार ने पशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए पशु औषधि केंद्र योजना की शुरूआत की है।
- सांसद बिष्णु पद रे ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव से मुलाकात कर द्वीपों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में तत्काल हस्तक्षेप की माँग की।
- 'प्रशासन गाँव की ओर' पहल के तहत मध्योत्तर अंडमान जिला में जन शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

लोकसभा ने कल कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2025 और आयकर संख्या 2 विधेयक, 2025 को धनिमत से पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए। आयकर संख्या 2 विधेयक, 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, जबकि कराधान विधि संशोधन विधेयक, 2025 आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करेगा साथ ही वित्त अधिनियम, 2025 में भी संशोधन करेगा।

&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

भारत सरकार ने देश भर में पशु स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत पशु औषधि केंद्र खोले जाएँगे। इस केंद्र के माध्यम से पशुपालकों को सस्ती और जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाइयाँ उपलब्ध होंगे। पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में गुणवत्तापूर्ण पशु औषधियाँ आसानी से उपलब्ध कराना है। ये केंद्र पंजीकृत प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों द्वारा खोले जा सकते हैं। इसके लिए आवेदक के पास कम से कम 120 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए। केन्द्र में बी. फार्मा या डी. फार्मा की डिग्री प्राप्त पंजीकृत फार्मासिस्ट की नियुक्ति और राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से दवा बिक्री लाइसेंस होना चाहिए। प्रति राजस्व ब्लॉक केवल एक केंद्र की अनुमति होगी।

योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस द्वीपसमूह में खोले गए केंद्रों के लिए डेढ़ लाख रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन उपलब्ध है। इसके अलावा, केंद्र द्वारा रखे गए स्टॉक, खरीदी और बेची गई दवाओं की संख्या के आधार पर 20,000 रुपये तक का मासिक मानदेय दिया जाएगा। इन केंद्रों पर केवल भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो द्वारा आपूर्ति की गई दवाएँ ही बेची जा सकेंगी। एथनो-पशु चिकित्सा उत्पाद और प्रमाणित पशु आहार भी बेचे जा सकते हैं। यह योजना पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता मंत्रालय और पीएमबीआई द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाती है। आवेदक पांच हजार रुपये शुल्क अदा कर डी ए एच डी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

<><><><><><><>

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पिछले दस वर्षों में भारत का मछली निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है और 30 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 60 हजार करोड़ रुपये हो गया है। श्री सिंह ने कहा कि चूंकि उनका मंत्रालय सोलहवें वित्त आयोग के लिए योजनाएँ तैयार कर रहा है, इसलिए मंत्रालय ने निर्यातिकों और राज्य प्रतिनिधियों विशेष रूप से उच्च निर्यात क्षमता वाले राज्यों के प्रतिनिधियों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है।

<><><><><><><>

हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिल्लीग्राउंड पुलिस थाना ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य संबद्ध विभागों के सहयोग से बाइक रैली का आयोजन किया। रैली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से शुरू होकर निम्बूडेरा बाजार होते हुए वापस स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचकर सम्पन्न हुई। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। “आज़ादी का अमृत महोत्सव” के तहत आयोजित इस रैली ने लगभग 45 प्रतिभागियों ने रैली में भाग लिया।

<><><><><><><>

द्वीपों के सांसद बिष्णु पद रे ने कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव से मुलाकात कर द्वीपसमूह में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति से अवगत कराते हुए तत्काल हस्तक्षेप की माँग की। बैठक के दौरान, सांसद ने पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित होने तक अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही स्तरों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया।

उन्होंने सचिव के समक्ष द्वीपसमूह के लिए स्वीकृत 50 विशेषज्ञ पदों में से केवल 6 पदों को भरे जाने, जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञों की कमी और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी दवाओं की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों को उठाया। सांसद ने इस संबंध में सचिव के सामने सुझाव रखे, जिसमें द्वीपसमूह में विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति की रोटेशन प्रणाली को बहाल करने, एम्स या पीपीपी मोड के माध्यम से अनिम्स के प्रबंधन में सुधारों में तेजी लाने, स्वास्थ्य सेवा की कमियों का मूल्यांकन और समाधान करने के लिए एक विशेषज्ञ टीम भेजने, विशेषज्ञ पदों में संरचनात्मक सुधारों को लागू करना शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने प्रशासन के मुख्य सचिव के परामर्श से इन मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया।



'प्रशासन गाँव की ओर' पहल के तहत मध्योत्तर अंडमान जिला उपायुक्त नंदिनी महाराज और सहायक आयुक्त विकास कुमार के नेतृत्व में जन शिकायतों के समाधान और लंबित पड़े मामलों में तेजी लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कदमतला के अपने यात्रा के दौरान, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और स्थानीय निवासियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया, जिसमें प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की गई और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। उन्होंने एक राजस्व शिविर न्यायालय का आयोजन किया, जहाँ उप-विभाजन, नाम सुधार, दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और इन मामलों से संबंधित आदेश क्षेत्र के निवासियों को वितरित किए गए। इस दौरान सुनील बिश्वास नामक कदमतला निवासी की भूमि से संबंधित मामले की समीक्षा कर उसमें सुधार के आदेश भी जारी किए गए। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने क्षेत्र की प्रमुख विकास परियोजनाओं के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।



नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से अगस्त माह में ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह शिविर सुबह साढ़े नौ से शाम चार बजे तक चलेंगे। दक्षिण अंडमान के विम्बलींगंज में आज शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कार निकोबार में भी कल से शिविर आयोजित किए जाएंगे। विभाग ने कहा है कि इस दौरान लाभार्थी आधार संबंधी कार्य करा सकते हैं।



श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के 24 वार्डों के लिए अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली गई है।

इन संशोधनों की सूची अंडमान निकोबार द्वीपसमूह नगरपालिका मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव संचालन नियम, 1995 के अनुसार तैयार की गई है। आम जनता के लिए संशोधनों की सूची सहित मतदाता सूची की एक प्रति मोहनपुरा स्थित नगरपालिका मुख्यालय, इंदिरा भवन में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा पंचायत और नगरपालिका चुनाव निदेशक कार्यालय और संबंधित तहसीलदार कार्यालयों में भी सूची निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस के प्रशिक्षुओं और 75वें बैच के भर्ती कांस्टेबलों द्वारा छोटे हथियारों से फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास पुलिस फायरिंग रेंज, बर्ड लाइन और प्रातरापुर में कल, उन्नीस और बीस अगस्त को सुबह 05:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित चलेगा। इस दौरान सभी संबंधितों से अपने मवेशियों और वाहनों को फायरिंग रेंज से दूर रखने को कहा गया है।

<><><><><><><>

राजकीय पॉलिटेक्निक डिग्लीपुर में प्रवेश के लिए उम्मीदवार कल से कॉमन कॉलेज प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 14 अगस्त को सुबह 9.30 बजे से परामर्श का आयोजन किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

<><><><><><><>